आर्थिक न्याय के ज्वलन्त राष्ट्रीय प्रश्न

(Burning National Question of Economic Justice)

1. यदि एक दिन में ही सम्पूर्ण आर्थिक भ्रष्टाचार, कालाधन, नकलीमुद्रा, टैक्सचोरी एवं अन्य समस्त मौद्रिक अपराध तथा मुद्रा की ढलाई, छपाई, ढुलाई, गिनाई, भण्डारण, सुरक्षा आदि पर किए जानेवाले भारी अपव्ययों का अन्त केवल **'डिजिटल करेंसी सिस्टम'** लागू करने से हो सकता है, तो राष्ट्रीय सरकार अथवा राजनैतिक व्यक्तियों एवं दलों अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों की ओर से इतनी चुप्पी, निष्क्रियता एवं उपेक्षा क्यों हो रही है? **'डिजिटल करेंसी सिस्टम'** लागू करने में इतना विलम्ब एवं टालमटोल क्यों हो रहा है?

   (जनता जागो! वर्तमान सरकारें, राजनेता एवं समाजनेता राष्ट्रहित एवं जनहित के विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। जनतन्त्र में जनहित की उपेक्षा कभी न्यायसंगत नहीं हो सकती। न्यायशील मौद्रिक नीति के अन्तर्गत 'आंकिक मुद्रा प्रणाली' की स्थापना द्वारा आर्थिक न्याय तुरन्त प्रतिष्ठित हो सकता है।)

2. यदि एक दिन में ही सम्पूर्ण पूँजीसंकट अर्थात् विदेशी एवं देशी ऋणसंकट, विदेशी एवं देशी विनियोगसंकट एवं अन्य विविध प्रकार के मौद्रिक संकटों का अन्त केवल **'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली'** लागू करने से हो सकता है, तो राष्ट्रीय सरकार अथवा राजनैतिक व्यक्तियों एवं दलों अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों की ओर से इतनी चुप्पी, निष्क्रियता एवं उपेक्षा क्यों हो रही है? **'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली'** लागू करने में इतना विलम्ब एवं टालमटोल क्यों हो रहा है?

   (जनता जागो! वर्तमान सरकारें, राजनेता एवं समाजनेता राष्ट्रहित एवं जनहित के विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। जनतन्त्र में जनहित की उपेक्षा कभी न्यायसंगत नहीं हो सकती। न्यायशील मौद्रिक नीति के अन्तर्गत किसी भी सम्पत्ति के बाजारमूल्य के समकक्ष द्रवीकरण सुलभ करानेवाली 'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली' की स्थापना द्वारा आर्थिक न्याय तुरन्त प्रतिष्ठित हो सकता है।)

3. यदि एक दिन में ही सम्पूर्ण मौद्रिक शोषण, अनुद्यमिता, धनध्रुवीकरण, धीमी मौद्रिक चलनगति एवं अन्य मौद्रिक अभिशापों का अन्त केवल **'निर्भार मुद्राप्रचालन प्रणाली'** लागू करने से हो सकता है, तो राष्ट्रीय सरकार अथवा राजनैतिक व्यक्तियों एवं दलों अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों की ओर से इतनी चुप्पी, निष्क्रियता एवं उपेक्षा क्यों हो रही है? **'निर्भार मुद्राप्रचालन प्रणाली'** लागू करने में इतना विलम्ब एवं टालमटोल क्यों हो रहा है?

   (जनता जागो! वर्तमान सरकारें, राजनेता एवं समाजनेता राष्ट्रहित एवं जनहित के विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। जनतन्त्र में जनहित की उपेक्षा कभी न्यायसंगत नहीं हो सकती। न्यायशील मौद्रिक नीति के अन्तर्गत मुद्रा पर सरकारी व्याज, टैक्स आदि भारों से मुक्त करनेवाली 'निर्भार मुद्राप्रचालन प्रणाली' की स्थापना द्वारा आर्थिक न्याय तुरन्त प्रतिष्ठित हो सकता है।)

4. यदि एक दिन में ही सम्पूर्ण राजस्व एवं कर प्रणाली की जटिलता, विसंगति, अपवंचन एवं अन्य कठिनाइयों का अन्त समस्त संसाधनों पर से राजस्व, लगान, ड्यूटी आदि हटाकर केवल सकल उत्पादन पर **'तृतीयांशी राजस्वनीति'** लागू करने से हो सकता है, तथा राजस्व एवं कर प्रणाली की समस्त समस्याएँ एवं दोष समाप्त हो सकते हैं, तो राष्ट्रीय सरकार अथवा

राजनैतिक व्यक्तियों एवं दलों अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों की ओर से इतनी चुप्पी, निष्क्रियता एवं उपेक्षा क्यों हो रही है? सकल उत्पादन पर **'तृतीयांशी राजस्वनीति'** लागू करने में इतना विलम्ब एवं टालमटोल क्यों हो रहा है?

   (जनता जागो! वर्तमान सरकारें, राजनेता एवं समाजनेता राष्ट्रहित एवं जनहित के विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। जनतन्त्र में जनहित की उपेक्षा कभी न्यायसंगत नहीं हो सकती। न्यायशील राजकोषीय नीति के अन्तर्गत सकल उत्पादन पर तृतीयांश राजस्व की सम्यक् एवं सुनिश्चित व्यवस्था द्वारा आर्थिक न्याय तुरन्त प्रतिष्ठित हो सकता है।)

5. यदि एक दिन में ही राजस्व एवं करवसूली के भारी अपव्ययों, कठिनाइयों एवं जटिलताओं का अन्त केवल राजस्व एवं कर वसूली की सरल, सहज, एकीकृत व्यवस्था को जन्म देनेवाली **'बैंक पर राजस्व कटौती की प्रणाली'** द्वारा हो सकता है, तो राष्ट्रीय सरकार अथवा राजनैतिक व्यक्तियों एवं दलों अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों की ओर से इतनी चुप्पी, निष्क्रियता एवं उपेक्षा क्यों हो रही है? **'बैंक पर राजस्व कटौती की प्रणाली'** लागू करने में इतना विलम्ब एवं टालमटोल क्यों हो रहा है?

   (जनता जागो! वर्तमान सरकारें, राजनेता एवं समाजनेता राष्ट्रहित एवं जनहित के विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। जनतन्त्र में जनहित की उपेक्षा कभी न्यायसंगत नहीं हो सकती। न्यायशील राजकोषीय नीति के अन्तर्गत 'आंकिक मुद्रा प्रणाली' लागू होने पर राजस्व अथवा कर की वसूली किसी भी लेन-देन पर 1% या 2% के रूप में सीधे 'बैंक पर कटौती' की व्यवस्था द्वारा आर्थिक न्याय तुरन्त प्रतिष्ठित हो सकता है।)

6. यदि एक दिन में ही सम्पूर्ण अशिक्षा, बेरोजगारी, असुविधा, असुरक्षा का अन्त केवल न्यायशील **'समानुपातिक बजटीकरण प्रणाली'** द्वारा हो सकता है, तो राष्ट्रीय सरकार अथवा राजनैतिक व्यक्तियों एवं दलों अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों की ओर से इतनी चुप्पी, निष्क्रियता एवं उपेक्षा क्यों हो रही है? न्यायशील **'समानुपातिक बजटीकरण प्रणाली'** लागू करने में इतना विलम्ब एवं टालमटोल क्यों हो रहा है?

   (जनता जागो! वर्तमान सरकारें, राजनेता एवं समाजनेता राष्ट्रहित एवं जनहित के विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। जनतन्त्र में जनहित की उपेक्षा कभी न्यायसंगत नहीं हो सकती। न्यायशील राजकोषीय नीति के अन्तर्गत 25% विद्याबजट, 25% जीविकाबजट, 25% सुविधाबजट, 25% संरक्षणबजट के रूप में 'समानुपातिक बजटीकरण' की स्थापना द्वारा चारों जनाधिकार तुरन्त प्रतिष्ठित हो सकते हैं।)

7. यदि एक दिन में ही सम्पदाओं पर स्वामित्व की विसंगति, एकाधिकार एवं अभाव जैसी भयंकर समस्याओं का अन्त केवल **'न्यायशील सम्पदानीति'** लागू करने से हो सकता है, तो राष्ट्रीय सरकार अथवा राजनैतिक व्यक्तियों एवं दलों अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों की ओर से इतनी चुप्पी, निष्क्रियता एवं उपेक्षा क्यों हो रही है? **'न्यायशील सम्पदानीति'** लागू करने में इतना विलम्ब एवं टालमटोल क्यों हो रहा है?

   (जनता जागो! वर्तमान सरकारें, राजनेता एवं समाजनेता राष्ट्रहित एवं जनहित के विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। जनतन्त्र में जनहित की उपेक्षा कभी न्यायसंगत नहीं हो सकती। न्यायशील सम्पदानीति के अन्तर्गत पात्रतानुसार कर्म, कर्मानुसार पद, पदानुसार सम्पदा की समुचित व्यवस्था द्वारा कृषिसम्पदा, वाणिज्यसम्पदा, राज्यसम्पदा एवं नेतृत्वसम्पदा के चार भिन्न स्वरूपों, प्रकारों एवं उन पर समुचित स्वामित्व की स्थापना से आर्थिक न्याय तुरन्त प्रतिष्ठित हो सकता है।)

8. यदि एक दिन में ही श्रमवाद, पूँजीवाद, राज्यवाद जैसी एकाधिकारी अर्थव्यवस्थाओं का अन्त केवल **'न्यायशील त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था'** पर आधारित उद्यमनीति लागू करने से हो सकता है, तो राष्ट्रीय सरकार अथवा राजनैतिक व्यक्तियों एवं दलों अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों की ओर से इतनी चुप्पी, निष्क्रियता एवं उपेक्षा क्यों हो रही है? आर्थिक उद्यमों पर **'न्यायशील त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था'** लागू करने में इतना विलम्ब एवं टालमटोल क्यों हो रहा है?

(जनता जागो! वर्तमान सरकारें, राजनेता एवं समाजनेता राष्ट्रहित एवं जनहित के विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। जनतन्त्र में जनहित की उपेक्षा कभी न्यायसंगत नहीं हो सकती। न्यायशील उद्यमनीति के अन्तर्गत त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के तीनों साधनों श्रम, पूँजी, सुविधा का समान महत्त्व एवं श्रमिक, पूँजीपति, सरकार की समाधिकारिता की स्थापना द्वारा आर्थिक न्याय तुरन्त प्रतिष्ठित हो सकता है।)

9. यदि एक दिन में ही कृषकों एवं वणिकों की भूमिहीनता, पूँजीहीनता, बेरोजगारी, निर्धनता, दरिद्रता अथवा गरीबी का अन्त केवल **'अक्षय जीविकाकोष की स्थापना'** द्वारा हो सकता है, तो राष्ट्रीय सरकार अथवा राजनैतिक व्यक्तियों एवं दलों अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों की ओर से इतनी चुप्पी, निष्क्रियता एवं उपेक्षा क्यों हो रही है? कृषकों एवं वणिकों के लिए **'अक्षय जीविकाकोष की स्थापना'** करने में इतना विलम्ब एवं टालमटोल क्यों हो रहा है?

(जनता जागो! वर्तमान सरकारें, राजनेता एवं समाजनेता राष्ट्रहित एवं जनहित के विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। जनतन्त्र में जनहित की उपेक्षा कभी न्यायसंगत नहीं हो सकती। न्यायशील समुचित रोजगार की व्यवस्था एवं अक्षय जीविकाकोष स्थापित करके भूमिहीन किसानों को भूमि, पूँजीहीन वणिकों को सरल एवं स्वैच्छिक किश्तों में वापसयोग्य विर्व्याज उधारी के रूप में निर्भर पूँजी की समुचित सुलभता द्वारा आर्थिक न्याय तुरन्त प्रतिष्ठित हो सकता है।)

10. यदि एक दिन में ही राजकीय पदों पर आर्थिक विषमता का अन्त केवल **'राजकीय पदों पर समान वेतन की नीति'** लागू करने से हो सकता है, तो राष्ट्रीय सरकार अथवा राजनैतिक व्यक्तियों एवं दलों अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों की ओर से इतनी चुप्पी, निष्क्रियता एवं उपेक्षा क्यों हो रही है? **'राजकीय पदों पर समान वेतन की नीति'** को स्थापित करने में इतना विलम्ब एवं टालमटोल क्यों हो रहा है?

(जनता जागो! वर्तमान सरकारें, राजनेता एवं समाजनेता राष्ट्रहित एवं जनहित के विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। जनतन्त्र में जनहित की उपेक्षा कभी न्यायसंगत नहीं हो सकती। न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था में चपरासी से राष्ट्रपति तक सभी राजकीय पदों पर समान वेतनमान एवं तत्सम भत्ते की समुचित व्यवस्था द्वारा आर्थिक न्याय तुरन्त प्रतिष्ठित हो सकता है।)

11. यदि एक दिन में ही वस्तियों के पिछड़ेपन का अन्त केवल **' प्रतिग्राम समुचित सरकारी सेवाओं की वितरण नीति एवं प्रतिग्राम समान संख्या में सरकारी एवं राजकीय कर्मचारियों की नियुक्ति'** द्वारा हो सकता है, तो राष्ट्रीय सरकार अथवा राजनैतिक व्यक्तियों एवं दलों अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों की ओर से इतनी चुप्पी, निष्क्रियता एवं उपेक्षा क्यों हो रही है? **'समुचित सेवाओं एवं सरकारी कर्मचारियों**

की समान संख्या में नियुक्ति की नीति' लागू करने में इतना विलम्ब एवं टालमटोल क्यों हो रहा है?

(जनता जागो! वर्तमान सरकारें, राजनेता एवं समाजनेता राष्ट्रहित एवं जनहित के विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। जनतन्त्र में जनहित की उपेक्षा कभी न्यायसंगत नहीं हो सकती। सभी व्यक्तियों के लिए प्रतिक्षेत्र आधार पर संतुलित संख्या में राजकीय वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं समुचित सार्वजनिक सेवाओं की स्थापना द्वारा आर्थिक न्याय तुरन्त प्रतिष्ठित हो सकता है।)

❁❁❁

अपील

न्यायधर्मसभा द्वारा समाज एवं राष्ट्र में न्याय की स्थापना के लिए कुल 111 न्यायशील प्रस्ताव घोषित किए गए हैं। आर्थिक न्याय को लेकर उपरोक्त ज्वलन्त प्रश्नावली द्वारा केवल 11 प्रस्तावों से सम्बन्धित सार्वजनिक प्रश्न उठाए गए हैं। वर्तमान सार्वभौमिक समाज एवं राष्ट्र के नागरिक अब शैक्षिक विकास के द्वारा प्रबुद्ध हो रहे हैं। अतः वे न्याय और अन्याय के लक्षणों को स्पष्ट देखने की क्षमता को प्राप्त हो रहे हैं। आर्थिक न्याय ही मानवजीवन का प्राथमिक न्याय है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक अथवा राष्ट्रीय व्यवस्था को अर्थव्यवस्था के नाम से ही जाना जाता है। अर्थव्यवस्था ही मानवीय समाज एवं राष्ट्र की आधारशिला है। अतः आर्थिक न्याय को मानवजीवन की प्राथमिक आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए। उपरोक्त कुल 111 न्यायशील प्रस्तावों में से 100 प्रस्तावों को छोड़कर केवल 11 अति महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रस्ताव यदि किसी समाज अथवा राष्ट्र में पारित व प्रतिष्ठित किए जा सकें, तो सम्पूर्ण मानवता को महान् समृद्धि एवं परम वैभव का वातावरण प्राप्त हो सकता है। अनाजीविका, बेरोजगारी, निर्धनता, दरिद्रता, गरीबी, भुखमरी, अभावग्रस्तता जैसी अमानवीय समस्याएँ वस्तुतः एक दिन में ही त्वरित रूप से समाप्त हो सकती हैं। अतः सभी प्रबुद्धजनों से अपील है कि वे उपरोक्त 11 प्रश्नों को सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र में तथाकथित उत्तरदायी अधिकारियों से पूछने का महान् कार्य करें। यह सम्पूर्ण मानवता की रक्षा के लिए अत्यन्तिम रूप से महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर में ही मानवता का आर्थिक हित छिपा हुआ है। यह दरिद्रता की अचूक औषधि है। अभाव पर प्रभाव की विजय का इन प्रश्नों में रहस्य छिपा हुआ है। इस रहस्य पर से पर्दा उठना आवश्यक है। अतः सभी प्रबुद्धजन इन रहस्यों को प्रकाशित करने में न्यायधर्मसभा के सहयोगी बनें।

❁❁❁

न्याय धर्म सभा, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार.
फो0 : 01334-244760, मो0 : 9319360554, 9997858988
website : www.nyayadharmsabha.org
email : info@nyayadharmsabha.org, nds.haridwar@gmail.com